भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4843

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा कृषिकार्य छोड़ना

4843. श्री गौतम गंभीरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कृषि कार्य छोड़ने वाले किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) इस समीक्षा में किसानों द्वारा कृषि छोड़ने के किन-किन मुख्य कारणों को चिन्हित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने सुझाव दिया है कि किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर नकदी फसलों की खेती करें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा के दौरान अन्य किन-किन कमियों को चिन्हित किया गया है तथा सरकार द्वारा कृषि को लोकप्रिय बनाने और यह सुनिश्चित करने कि किसान निकट भविष्य में कृषि कार्य न छोड़े, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): भारत के महापंजीकार द्वारा संचालित जनगणना के अनुसार, देश में कृषकों की कुल संख्या 2001 में 127.3 मिलियन से कम होकर 2011 में 118.8 मिलियन कृषक हो गई है। जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार कृषकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

चूंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद संचालित होती है, इसलिए 2011 से कृषि को छोड़कर अन्य पेशों में जाने वाले किसानों का ब्यौरा ज्ञात नहीं है।

(घ): किसान स्वयं उपभोग प्रवृत्तियों में बदलावों और बाजार के उतार चढ़ावों के मद्देनज़र विभिन्न अनाज फसलों और/या नकदी फसलों के लिए खेती के अधीन क्षेत्र का निर्णय करते हैं। तथापि, सरकार कृषि परिवारों के आय आधार के विविधिकरण हेतु बागवानी, फूलों की खेती,

मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है।

(ङ)किसानों के लिए कृषि को आकर्षक और अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें, अन्य योजनाओंके साथ-साथ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना; राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा); एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फसलों के उत्पादन के अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर 50 प्रतिशत के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने का सिद्धांत अपनाया है।

इसके अलावा, पूरे देश में सभी कृषक परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामत: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य उच्चतम आय समूहों से संबंधित कतिपय अपवंजनों के अधीन प्रत्येक किसान को 2,000 रूपए की तीन किश्तों में 6,000 रूपए सालानाका भुगतान करना है।

अनुबंध

दिनांक 230.7 2019.को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4843 के भाग के (ग) से (क) खित अनुबंधर में उल्लिउत्त

भारत में कृषि कामगारों की संख्या मिलियन में))

क्र.सं.	राज्यसंघ/ राज्य क्षेत्र	कृषक	
		2001	**2011**
	अखिल भारत	**127.31**	**118.81**
1	जम्मू और कश्मीर	1.59	1.25
2	हिमाचल प्रदेश	1.95	2.06
3	पंजाब	2.07	1.93
4	चंडीगढ़	0.00	0.00
5	उत्तराखंड	1.57	1.58
6	हरियाणा	3.02	2.48
7	दिल्ली	0.04	0.03
8	राजस्थान	13.14	13.62
9	उत्तर प्रदेश	22.17	19.06
10	बिहार	8.19	7.20
11	सिक्किम	0.13	0.12
12	अरुणाचल प्रदेश	0.28	0.30
13	नागालैंड	0.55	0.54
14	मणिपुर(3 उपप्रभागों को छोड़कर-)	0.38	0.57
15	मिजोरम	0.26	0.23
16	त्रिपुरा	0.31	0.30
17	मेघालय	0.47	0.49
18	असम	3.73	4.06
19	पश्चिम बंगाल	5.65	5.12
20	झारखंड	3.89	3.81
21	ओडिशा	4.25	4.10
22	छत्तीसगढ़	4.31	4.00
23	मध्यप्रदेश	11.04	9.84
24	गुजरात	5.80	5.45
25	दमन और दीव	0.00	0.00
26	दादरा एवं नगर हवेली	0.04	0.03
27	महाराष्ट्र	11.81	12.57
28	आंध्र प्रदेश	7.86	6.49
29	कर्नाटक	6.88	6.58
30	गोवा	0.05	0.03
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00
32	केरल	0.72	0.67
33	तमिलनाडु	5.12	4.25
34	पुदुचैरी	0.01	0.01
35	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.02

टिप्पनणी: भारत और मणिपुर के लिए जनगणना 2001 के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के माओ परम, पाओमाता और पुरुल उप प्रभाग शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारत के महापंजीकार

*****